NYCS

युवा सहकार

www.nycsindia.com

सितंबर 2024, नई दिल्ली

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति

बढ़ेगी समृद्धि

Did You Know?

2025 is the International Year of Cooperatives!

The UN declared 2025 as a year to celebrate cooperatives around the world. Cooperatives are businesses owned by their members, focusing on both profit and the needs of their communities. They play a big role in sustainable development and achieving the UN's Sustainable Development Goals by 2030.

There will be a year-long celebration to raise awareness about cooperatives and their positive impact.

युवा सहकार

वर्ष : 01, अंक-03, सितंबर-2024

निदेशक मंडल

एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं पारस ऑफसेट प्रा. लि. कुंडली, हरियाणा द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमार: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

सहकारिता बदलेगी युवाओं की तकदीर 04
दुनियाभर में सहकारिता आंदोलन को मिलेगी मजबूती 05
नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति: बढ़ेगी समृद्धि 06
युवाओं के कौशल विकास से हासिल होगा विकसित भारत का लक्ष्य 12
युवाओं की ऊर्जा से सपने होंगे साकार 14

16
स्किल डवलपमेंट पर एनवाईसीएस का फोकस

18
युवाओं को सशक्त बनाने की पहल

सहकारिता में बढ़ रही युवाओं की भागीदारी 20
बिना बिचौलिए लाभार्थियों को मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ 21
कौशल विकास के लिए फ्लिपकार्ट से एमओयू 26
गांवों में घर-घर पानी पहुंचाएगी पैक्स 28
गली-गली में शोर है, गली क्रिकेट का जोर है 30

सहकारिता बदलेगी युवाओं की तकदीर

पिछले कुछ वर्षों में सहकारिता आंदोलन में युवाओं और महिलाओं की भूमिका पूरी तरह से बदल रही है। इसकी वजह से सहकारिता में नवाचार और नए उद्यमों का संचार हुआ है। युवाओं और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से सहकारिता क्षेत्र में अभूतपूर्व परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसने तेजी से बदल रही दुनिया में इस क्षेत्र के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है। भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने एवं इसे ग्रामीण समाज के आर्थिक एवं बुनियादी विकास का आधार बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'सहकार से समृद्धि' की संकल्पना की है। 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक उल्लेखनीय पहल की हैं जिनमें नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने का महत्वपूर्ण कदम भी शामिल है।

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का उद्देश्य 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करना, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करना और देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना है। सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्द्धन कर सहकारिता क्षेत्र को उसकी क्षमता हासिल करने में सहायता करना और सहकारिता क्षेत्र के लिए नीतिगत, कानूनी और संस्थागत अवसंरचना का निर्माण करना भी इस नीति का मकसद है।

सहकारिता क्षेत्र का प्रभाव देश में व्यापक रूप से बढ़ रहा है। सहकारी क्षेत्र के विकास पर ही देश का विकास निर्भर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत सरकार सहकारी आंदोलन को निरंतर गति, विस्तार एवं दिशा दे रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इसे इस बात से भी बखूबी समझा जा सकता है कि देश में 29 करोड़ सदस्यों के साथ 8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद पिछले तीन वर्षों में सरकार ने दूरगामी महत्व के बहुत से बदलाव किए हैं। इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

नई सहकारिता नीति में सभी के लिए भागीदारी सुनिश्चित की गई है। खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। यह न केवल उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा, बल्कि उनमें सहकारिता की भावना भी मजबूत होगी।

नई सहकारिता नीति में सभी के लिए भागीदारी सुनिश्चित की गई है। खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। यह न केवल उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा, बल्कि उनमें सहकारिता की भावना भी मजबूत होगी। सहकारिता के मौजूदा मॉडल में आबादी के ये दो महत्वपूर्ण हिस्से नदारद थे। युवा आबादी के लिए अवसरों के ज्यादा से ज्यादा द्वार खोलने और सकारात्मक उत्पादकता के साथ उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि उनके अनुकूल नीतियां बनाई जाएं। नई नीति के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र को व्यवस्थित करने और ग्रामीण क्षेत्रों के चौतरफा विकास में भी मदद मिलेगी।

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनेगा 2025

भारत करेगा वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की मेजबानी

युवा सहकार टीम

इफको लिमिटेड के एमडी डॉ. उदय शंकर अवस्थी, केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी और आईसीए के महानिदेशक जेरोन डगलस (बाएं से दाएं)।

भारत में सहकारिता क्षेत्र की सफलता की धमक अब वैश्विक स्तर पर सुनाई देने लगी है। संभवतः यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारी एसोसिएशन (आईसीए) पहली बार भारत में वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन करा रहा है। छह दिन तक चलने वाले वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन इस वर्ष 25-30 नवंबर को नई दिल्ली में होगा। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होने वाले इस सम्मेलन के आयोजन की जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको को मिली है। इफको ने ही यह सम्मेलन भारत में कराने का प्रस्ताव दिया था। आईसीए के 130 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब एसोसिएशन की महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन भारत में हो रहा है।

हाल ही में भारत के दौरे पर आए आईसीए के महानिदेशक जेरोन डगलस ने बताया कि इस वर्ष के सम्मेलन का विषय 'सहकारिताएं: सबकी समृद्धि का द्वार' रखा गया है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण 'सहकार से समृद्धि' के अनुरूप है। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आधिकारिक शुभारंभ भी होगा। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहकारिता की भूमिका को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहा है।

डगलस ने कहा कि आईसीए का संस्थापक सदस्य होने के नाते सहकारी समितियों की संख्या और उनके विस्तार की संभावनाओं के मामले में भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है। वैश्विक सहकारी आंदोलन में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दुनिया में लगभग 30 लाख सहकारी समितियां हैं जिनमें संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी सदस्य देशों के एक अरब से अधिक सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सहकारी आंदोलन सबसे अधिक स्थिर और टिकाऊ मॉडल साबित हुआ है। आने वाले समय में दुनिया का संकटों की एक श्रृंखला से सामना हो सकता है।

> **भारत में पहली बार होने वाला यह वैश्विक सम्मेलन कार्बन न्यूट्रल होगा। इसके लिए 10 हजार पीपल के पौधे लगाये जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए सम्मेलन में शाकाहारी व्यंजन परोसे जाएंगे।**

केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी कहते हैं कि भारतीय सहकारी आंदोलन के विकास और वृद्धि के लिए सहकारिता मंत्रालय की 54 नई पहलों की वजह से भारत सबसे तेजी से बढ़ते सहकारी क्षेत्रों में से एक बन गया है। सबसे बड़ा परिवर्तन पैक्स मॉडल बायलॉज का कार्यान्वयन रहा। इस सम्मेलन से 'सहकार से समृद्धि' का विचार अब पूरे विश्व में फैलेगा। इफको लिमिटेड के एमडी डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने कहा कि भारतीय सहकारिता आंदोलन हमेशा से ही पर्यावरण की रक्षा के लिए सांस्कृतिक रूप से प्रेरित रहा है। इसी विरासत को जारी रखते हुए यह वैश्विक आयोजन कार्बन न्यूट्रल होगा। उन्होंने कहा कि संभावित कार्बन उत्सर्जन की भरपाई के लिए 10 हजार पीपल के पौधे लगाए जाएंगे जो अच्छे कार्बन अवशोषक हैं।

वैश्विक सहकारी सम्मेलन में भूटान के माननीय प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक परिषद (यूएन ईसीओएसओसी) के अध्यक्ष, आईसीए के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि, आईसीए सदस्य, भारतीय सहकारी आंदोलन के प्रमुख तथा 100 से अधिक देशों के 1500 प्रतिष्ठित अतिथियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस वैश्विक सम्मेलन में भारतीय गांवों की थीम पर बने 'हाट' में भारतीय सहकारी उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन भी किया जाएगा।

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति
बढ़ेगी समृद्धि

युवा सहकार टीम

भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने एवं इसे ग्रामीण समाज के आर्थिक एवं बुनियादी विकास का आधार बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'सहकार से समृद्धि' की संकल्पना की है। 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में केंद्र सरकार ने अनेक उल्लेखनीय

नई नीति से सशक्त बनेगा सहकारी आंदोलनः अमित शाह

सहकारी क्षेत्र को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, ''प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहकारी क्षेत्र को निरंतर विस्तार देकर ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत बना रहे हैं। बजट में 'राष्ट्रीय सहकारिता नीति' के निर्माण की घोषणा, देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही, मत्स्य सहकारिता को झींगा की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा से नई गति मिलेगी।''

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का उद्देश्य सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करना, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करना और देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना है। सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्द्धन कर सहकारिता क्षेत्र को उसकी क्षमता हासिल में सहायता करना और सहकारिता क्षेत्र के लिए नीतिगत, कानूनी और संस्थागत अवसंरचना का निर्माण करना भी इस नीति का मकसद है। सहकारिता क्षेत्र का प्रभाव देशभर में व्यापक रूप से बढ़ रहा है। सहकारी क्षेत्र के विकास पर ही देश का विकास निर्भर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत सरकार सहकारी आंदोलन को निरंतर गति, विस्तार एवं दिशा दे रही है।

> **राष्ट्रीय सहकारिता नीति के निर्माण की घोषणा, देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करने का काम करेगी।**
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

पहल की हैं जिनमें नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने का महत्वपूर्ण कदम भी शामिल है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय जल्दी ही नई सहकारिता नीति घोषित करेगा। वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने की घोषणा की है।

नई सहकारिता नीति में सभी के लिए भागीदारी सुनिश्चित की गई है। खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। यह न केवल उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा, बल्कि उनमें सहकारिता की भावना भी मजबूत होगी। सहकारिता के मौजूदा मॉडल में आबादी के ये दो महत्वपूर्ण हिस्से नदारद थे। सहकारिता आंदोलन से युवाओं को जोड़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अब युवाओं का देश है। युवा आबादी के लिए अवसरों के ज्यादा से ज्यादा द्वार खोलने और सकारात्मक उत्पादकता के साथ उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि उनके अनुकूल नीतियां बनाई जाएं। नई नीति के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र को व्यवस्थित करने और ग्रामीण क्षेत्रों के चौतरफा विकास में भी मदद मिलेगी।

बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिसका सीधा असर सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं को होगा। बजटीय प्रावधानों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को तेज करने में मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता विकसित होगी, जिससे सहकारी क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कोऑपरेटिव आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से सहकारी आंदोलन को मजबूती मिलेगी जिससे जमीनी स्तर पर लोगों को पर्याप्त लाभ मिल सकता है।

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा

नई सहकारिता नीति के प्रमुख उद्देश्य

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करना
- बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करना
- सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना
- सहकारिता क्षेत्र को उसकी क्षमता हासिल करने में सहायता करना
- सहकारिता क्षेत्र के लिए नीतिगत, कानूनी संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना

सहकारिता आधारित मॉडल से तेज होगा आर्थिक एवं सामाजिक विकास

सहकारिता क्षेत्र का सामर्थ्य बढ़ाने और इसे गति एवं नई ऊर्जा प्रदान करने के माध्यम से 'सहकार से समृद्धि' एवं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की आकांक्षा से करीब तीन साल पहले स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। सहकारिता को विकसित भारत का एक सशक्त माध्यम बनाने और गांवों, किसानों एवं जरूरतमंद वर्गों के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने की दिशा में यह एक अनूठा प्रयास है। मंत्रालय देश में सहकारी समितियों के हितों की देख-रेख और उनके उत्थान के लिए काम कर रहा है। इसके लिए अलग से प्रशासनिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा तैयार किया गया है जिससे देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती दी जा रही है। यह मंत्रालय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और देश के पहले सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सभी राज्यों और हित धारकों के साथ मिलकर निरंतर उद्यमशीलता से प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सहकारी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने और इसे आर्थिक-सामाजिक विकास के एक सशक्त मॉडल के रूप में स्थापित करने के साथ ही इसे कॉरपोरेट सेक्टर के समान बनाने के लिए सरकार और मंत्रालय की ओर से अब तक करीब 60 बड़ी पहल की गई हैं।

सहकारिता आंदोलन से युवाओं को जोड़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत अब युवाओं का देश है। युवा आबादी के लिए अवसरों के ज्यादा से ज्यादा द्वार खोलने और सकारात्मक उत्पादकता के साथ उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि उनके अनुकूल नीतियां बनाई जाएं।

तैयार हो कर सरकार के अनुमोदन के लिए विचाराधीन है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप नई नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सितंबर 2022 में एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में इस राष्ट्रीय समिति का गठन किया। कमेटी में विभिन्न राज्यों तथा देश भर से लिए गए विशेषज्ञों एवं हितधारकों सहित 49 सदस्यों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ समिति ने अब तक 17 बैठकें और चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन कर लिया है। समिति की ओर से तैयार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर मसौदा रिपोर्ट प्राप्त हो चुका है। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार हो जाने से सहकारी क्षेत्र को नई राह मिल जाएगी।

नई नीति की जरूरत क्यों

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई सहकारी नीति की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि वर्तमान सहकारिता नीति 2002 में तैयार की गई थी। ऐसे में, बदलते आर्थिक परिदृश्य के मद्देनजर एक नई नीति की आवश्यकता है। भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं और इनके सदस्यों की संख्या करीब 29 करोड़ है। ये सहकारी समितियां कृषि, प्रसंस्करण उद्योग, डेयरी उद्योग, गृह निर्माण, ऋण वितरण एवं विपणन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

इस संदर्भ में केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का भी स्पष्ट अभिमत है कि सहकारी क्षेत्र भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। नई सहकारी नीति के माध्यम से सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए भारत सरकार देश के राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी। श्री अमित शाह ने एक समारोह में कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर आएगी, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। केंद्र सरकार की प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक और दुग्ध उत्पादक संघ स्थापित करने की योजना है। आगामी कुछ वर्षों में देशभर में दो लाख ग्राम पंचायतों में बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) स्थापित करने की भी योजना है। सहकारी क्षेत्र ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाने के साथ देश में 1100 नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन किया जाएगा। देश के ज्यादातर पैक्स ने नये मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर अपने यहां लागू कर लिया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राज्य

सहकारी बैंकों से पैक्स और अन्य सहकारी संस्थाओं के लिए जिला या राज्य सहकारी बैंकों में अपने खाते खोलने की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया है जिससे सहकारिता मजबूत होगी। सहकारिता मंत्रालय ने देश के प्रत्येक राज्य में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) के माध्यम से सहकारी संस्थाओं को वित्तीय मदद मुहैया कराने का प्रावधान किया है। उनकी कारोबारी जरूरतों के हिसाब से उन्हें सहायता पहुंचाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। सहकारिता मंत्रालय ने ऐसे जिलों को भी सहकारी बैंकों से जोड़ने का प्रावधान किया है जो जिले अभी तक सहकारी बैंकों से कवर नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे जिलों में नाबार्ड से सहकारी बैंकों को पूर्ण कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से नए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक खोलने की योजना तैयार की जा रही है।

नीति के लिए समिति

नीति के मसौदे के लिए केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों, राष्ट्रीय सहकारी संघों, संस्थानों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए और इस संदर्भ में विभिन्न हितधारकों और आम जनता से हजारों सुझाव भी मिले। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाने के लिए देशभर से चुने गए विभिन्न हितधारक जैसे- राज्य सहकारिता विभागों, केंद्रीय मंत्रालयों के विभागों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शीर्ष सहकारी उर्वरक संगठन इफको, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ), राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक संघ (एनएएफसीएआरडी), नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड (एनएएफसीयूबी-नैफकब), कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको), नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (एनएफसीएसएफ), देश में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष संगठन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नैफेड) जैसे राष्ट्रीय महासंघ और विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विशेषज्ञ शामिल किए गए। इस विशिष्ट समिति ने सभी एकत्रित फीडबैक, नीतिगत सुझावों और सिफारिशों का विश्लेषण कर सहकारिता को नई दिशा देने के लिए गंभीर प्रयास किया है।

सर्वोत्तम प्रथाओं पर मंथन

सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों के सहकारिता मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों सहित सहकारिता सचिव, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, अपर सचिव, प्रमुख सचिवों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार आदि अनेक वरिष्ठ

राज्यवार सहकारी समितियां

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कोऑपरेटिव की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2,219
2.	आंध्र प्रदेश	17,812
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,197
4.	असम	11,149
5.	बिहार	26,640
6.	चंडीगढ़	476
7.	छत्तीसगढ़	9,412
8.	दिल्ली	5,943
9.	गोवा	5,458
10.	गुजरात	81,596
11.	हरियाणा	32,519
12.	हिमाचल प्रदेश	5,169
13.	जम्मू-कश्मीर	8,863
14.	झारखंड	11,456
15.	कर्नाटक	44,854
16.	केरल	6,103
17.	लद्दाख	262
18.	लक्षद्वीप	42
19.	मध्य प्रदेश	52,202
20.	महाराष्ट्र	2,22,067
21.	मणिपुर	11,258
22.	मेघालय	2,705
23.	मिजोरम	1,229
24.	नगालैंड	8,118
25.	ओडिशा	7,578
26.	पुडुचेरी	458
27.	पंजाब	19,016
28.	राजस्थान	36,875
29.	सिक्किम	3,795
30.	तमिलनाडु	22,030
31.	तेलंगाना	60,112
32.	दादरा, नगर हवेली और दमन एवं दीव	535
33.	त्रिपुरा	3,142
34.	उत्तर प्रदेश	43,560
35.	उत्तराखंड	5334
36.	पश्चिम बंगाल	31,234
	कुल	8,02,418

स्रोतः राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

क्षेत्रवार सहकारी समितियां

क्रम संख्या	क्षेत्र	कोऑपरेटिव की संख्या
1.	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	26863
2.	एग्रो प्रोसेसिंग/इंडस्ट्रियल	22837
3.	मधुमक्खी पालन	328
4.	उपभोक्ता	21220
5.	ऋण एवं मितव्ययिता सोसायटी	80128
6.	डेयरी	142014
7.	शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण	396
8.	किसान सेवा सोसायटी (एफएसएस)	514
9.	मत्स्यिकी	25717
10.	हस्तशिल्प	5067
11.	हथकरघा वस्त्र एवं बुनकर	19608
12.	हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी	191853
13.	जूट एवं क्वायर	56
14.	श्रमिक	44659
15.	लार्ज एरिया मल्टीपर्पस सोसायटी	5499
16.	पशुपालन एवं मुर्गी पालन	16685
17.	मार्केटिंग	9147
18.	मिसलेनियस क्रेडिट	5591
19.	मिसलेनियस नॉन क्रेडिट	30496
20.	मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव	20020
21.	प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स)	98875
22.	रेशम	498
23.	सामाजिक कल्याण एवं संस्कृति	2063
24.	चीनी मिल	285
25.	पर्यटन	459
26.	परिवहन	4160
27.	जनजाति-एस/एसटी	1471
28.	अर्बन कोऑपरेटिव बैंक	1340
29.	महिला कल्याण सहकारी समिति	24569
	कुल	802418

स्रोतः राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

अधिकारियों से भी विचार-विमर्श किया। देश में सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल को गति देने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को एक-दूसरे के साथ साझा किया। सहकारी वित्त पोषण के क्षेत्र में अग्रणी होने के नाते राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने राज्यों में अपने क्षेत्रीय निदेशालयों के माध्यम से सुविधा के साथ सहकारी क्षेत्र को ऋण देने की संभावनाओं और अवसरों के बारे में भी जानकारी साझा की। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि सहकारी समितियों को अन्य आर्थिक रूपों के समान माना जाए। प्रस्तावित नई सहकारिता नीति का उद्देश्य सहकारी समितियों की पहुंच को जमीनी स्तर तक बढ़ाना और सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना है। इसके संदर्भ में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से रायशुमारी और इनके विचारों को समाहित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों, विभिन्न हितधारक पक्षों, सहकारी संघों और यूनियनों के साथ भी कई दौर की चर्चा की है।

अब जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति को लाने की घोषणा कर दी है, तो समिति से जुड़े लोगों एवं विशेषज्ञों का मानना है कि अगले एक-दो महीनों में ही राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों, राष्ट्रीय सहकारी समितियों आदि सभी हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद नई सहकारिता नीति को लागू करने की घोषणा होने की संभावना है। उम्मीद है कि सरकार शीघ्र ही नई नीति के दस्तावेज पर अपनी निर्णायक मुहर लगाएगी और देश में बहुत जल्द ही नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का ऐलान हो जाएगा। इस निर्णय के साथ ही सहकारिता क्षेत्र के विकास का एक नया आयाम स्थापित होगा। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के निर्माण से 'सहकारिता से समृद्धि' की अवधारणा को साकार करने, सहकारी आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देने, देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रभु के अनुसार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का देश की जीडीपी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और देश को आगे बढ़ाने में यह नीति बहुत कारगर साबित होगी।

बजट ने फूंका सहकारी चीनी मिलों में दम

युवा सहकार टीम

आम बजट में सहकारी क्षेत्र के लिए किए गए अन्य प्रावधानों के मुताबिक, सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपये तक का रियायती ऋण मुहैया कराएगी। इसके लिए सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को 1000 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करेगा, जिसे वह 500-500 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दो किस्तों में अनुदान के रूप में देगा।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार ने आम बजट में 500 करोड़ रुपये का बंदोबस्त किया है, जिससे देश की 67,930 सक्रिय पैक्स की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। कंप्यूटरीकरण से पैक्स के कामकाज में दक्षता, लाभप्रदता, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी। इसी के साथ कृषि ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का भी पूर्ण कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) के कार्यालय का कंप्यूटरीकरण करने की योजना पर कार्य चल रहा है। इसका उद्देश्य एआरडीबी और आरसीएस की दक्षता, लाभप्रदता और पारदर्शिता के साथ जवाबदेही को बढ़ाना है। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधनों को कुशल, योग्य और मजबूत बनाने के लिए शिक्षण व प्रशिक्षण पर पूरा जोर दिया है। इसी के तहत राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान बैकुंठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैमनीकॉम) को ढांचागत रूप से सुदृढ़ करने के लिए आम बजट में विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) देश में सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण की निगरानी और मूल्यांकन का दायित्व निभाता है। आम बजट में इसके लिए वित्तीय अनुदान आवंटित किया गया है।

दरअसल, सहकारी प्रशिक्षण के माध्यम से मौजूदा सहकारी प्रशिक्षण संरचना को मजबूत बनाने और प्रशिक्षण प्रणाली के आधुनिकीकरण की सख्त जरूरत है। प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य प्रतिभागियों, पैक्स, डेयरी व मत्स्य समितियों, डीसीसीबी, एसीबी और राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय संघों के अधिकारियों को सहकारी मंत्रालय की योजनाओं से परिचित कराना है। इसके लिए पायलट परियोजना चलाई जाएगी। सरकार ने आम बजट में सहकारिता क्षेत्र की दो योजनाओं की पायलट परियोजना का प्रावधान किया है जिसमें सहकारी शिक्षा के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार करना शामिल है। इसके लिए टोकन मनी का प्रस्ताव किया गया है।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार ने आम बजट में 500 करोड़ रुपये का बंदोबस्त किया है, जिससे देश की 67,930 सक्रिय पैक्स की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। कंप्यूटरीकरण से पैक्स के कामकाज में दक्षता, लाभप्रदता, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी।

युवाओं के कौशल विकास से हासिल होगा विकसित भारत का लक्ष्य

बदलते वैश्विक माहौल में बढ़ा कौशल विकास का महत्व, खुले रोजगार के नए अवसर

उद्योग की जरूरत के मुताबिक कौशल को नई ताकत देना चाहती है सरकार

युवा सहकार टीम

वर्ष 2024-25 के बजट और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस वर्ष के संबोधन से स्पष्ट है कि सरकार विकसित भारत के अपने लक्ष्य को युवाओं की भागीदारी के साथ पूरा करेगी। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अब सरकार का फोकस युवाओं पर है। बजट में किये गये प्रावधान और प्रधानमंत्री के भाषण में युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता झलकती है। सरकार मानती है कि अब युवाओं को न सिर्फ शिक्षित बनाने, बल्कि उनका कौशल विकास कर उन्हें भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने की आवश्यकता है। इसे देखते हुए ही सरकार ने युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके माध्यम से युवा हुनरमंद बनकर रोजगार के अवसरों का तो फायदा उठा ही रहे हैं, वे स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित हो रहे हैं। स्वरोजगार करने वाले युवा दूसरे युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करा रहे हैं। युवाओं का कौशल विकसित करने के पीछे सरकार की सोच यह भी है कि आज का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। इसके अलावा, देश ही नहीं, बल्कि विदेशी श्रम बाजार में भी उसकी पूछ बढ़े।

युवा, महिला, गरीब और किसान केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। इनके उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं एवं कार्यक्रम चला रखे हैं। इन्हीं में से एक है स्किल इंडिया कार्यक्रम जिसके तहत देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले जा रहे हैं। इस साल के बजट में सरकार ने अगले पांच वर्ष में 20 लाख युवाओं का कौशल विकास करने के लिए एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। आज विश्व में जिस प्रकार का बदलाव नजर आ रहा है, उसमें कौशल का महत्व बहुत बढ़ गया है। यही वजह है कि सरकार कौशल को नई ताकत देना चाहती है ताकि उद्योग की जरूरतों के मुताबिक कौशल विकास किया जा सके। इसे देखते हुए ही स्किल इंडिया प्रोग्राम को इस बार बजट में व्यापक रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि जब तक युवाओं की चुनौतियों का व्यापक समाधान नहीं होगा विकसित भारत का सपना अधूरा रह जाएगा।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ''आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं। रोजगार के अनगिनत नए अवसर आज उनके दरवाजे पर दस्तक

दे रहे हैं। देश के युवाओं का इरादा अब धीरे-धीरे चलने का नहीं है। वे छलांग मारने के मूड में हैं और छलांग मार कर नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में हैं। यह भारत के लिए स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर को हमें जाने नहीं देना चाहिए। इस मौके को पकड़ कर अपने सपने और संकल्पों को लेकर चल पड़ेंगे तो हम विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य पूरा करके रहेंगे।''

प्रधानमंत्री ने कहा, ''हम कौशल को एक नई ताकत देना चाहते हैं। इसलिए इस बार के बजट में स्किल इंडिया प्रोग्राम को बहुत व्यापक रूप से लेकर आए हैं। इस बजट में इंटर्नशिप पर भी हमने बल दिया है, ताकि हमारे नौजवानों को एक एक्सपिरिएंस मिले, उनकी कैपिसिटी बिल्डिंग हो और बाजार में उनकी ताकत दिखाई दे, इस प्रकार से मैं स्किल्ड युवाओं को तैयार करना चाहता हूं। विश्व की परिस्थितियों को देखते हुए आज मैं साफ-साफ देख रहा हूं कि भारत का स्किल्ड मैनपावर, हमारे स्किलफुल नौजवान ग्लोबल जॉब मार्केट में अपनी धमक बनाएं, हम उस सपने को लेकर आगे चल रहे हैं।''

घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में असीमित संभावनाओं को देख आज देश का युवा आकांक्षाओं से भरा हुआ है। देश का नौजवान नई सिद्धियों को चूमना चाहता है। नए-नए शिखरों पर वह कदम रखना चाहता है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि हर सेक्टर में कार्य को तेज गति दी जाए और हर सेक्टर में नए अवसर पैदा किए जाएं। इसी की बदौलत रोजगार और स्वरोजगार के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं जिससे प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। इसका असर ग्लोबल ग्रोथ पर भी पड़ा है जिसमें भारत का बड़ा योगदान है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार पहले से दोगुना हुआ है। ग्लोबल संस्थानों का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है।

महिला स्वयं सहायता समूहों की सफलता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं इन समूहों में जुड़ी हैं। यह गर्व का विषय है कि गांव की सामान्य परिवार की 10 करोड़ महिलाएं इनसे जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, तब परिवार की निर्णय प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती हैं और एक बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन की गारंटी लेकर आती हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने अब स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपये तक का कर्ज देने का निर्णय किया है। पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी। बैंकों के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को अब तक 9 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं जिसकी मदद से वे अपने विभिन्न कामों को आगे बढ़ा रही हैं।

इसी तरह, पर्यटन का क्षेत्र हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टम बन रहा है जो युवाओं को आकर्षित कर रहा है। युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर भी उभरता हुआ क्षेत्र है। आज सैंकड़ों स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में आ रहे हैं जिससे युवाओं के लिए नए द्वार खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं।■

आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं। देश के युवाओं का इरादा अब धीरे-धीरे चलने का नहीं है। वे छलांग मारने के मूड में हैं और छलांग मार कर नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में हैं। यह भारत के लिए स्वर्णिम अवसर है। इस मौके को पकड़ कर अपने सपने और संकल्पों को लेकर चल पड़ेंगे तो हम विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य पूरा करके रहेंगे।

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

युवाओं की ऊर्जा से सपने होंगे साकार

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर अहमदाबाद में आयोजित 'इम्पैक्ट विद यूथ कॉन्क्लेव' में शामिल हुए केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया।

इस वर्ष की थीम 'क्लिक से प्रगति तकः सतत विकास के लिए युवाओं की डिजिटल राह' इस बात पर जोर देती है कि कैसे डिजिटलीकरण हमारी दुनिया को बदल रहा है और सतत विकास में तेजी लाने के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान कर रहा है।

युवा सहकार टीम

पिछले कुछ वर्षों से भारतीय युवाओं की धमक दुनिया भर में सुनाई दे रही है। युवाओं की ऊर्जा, उनका नवाचार और समर्पण उनके सपने को साकार करने में मददगार हैं। आजादी के 100 वर्ष पूरा होने के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस (12 अगस्त) के मौके पर गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ये विचार व्यक्त किए। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की थीम 'क्लिक से प्रगति तकः सतत विकास के लिए युवाओं की डिजिटल राह' थी।

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आयोजित 'इम्पैक्ट विद यूथ कॉन्क्लेव 2024' को संबोधित करते हुए डॉ. मांडविया ने विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, 'युवा सिर्फ कल के नेता ही नहीं, बल्कि आज के परिवर्तन के वाहक भी हैं। आपकी ऊर्जा और आपका नवाचार एवं समर्पण माननीय प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की कुंजी हैं।' इस कॉन्क्लेव का आयोजन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र भारत, यूनिसेफ, यूनिसेफ युवाह और एलिक्सिर फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के प्रति समर्पित सैकड़ों उत्साही युवाओं ने भाग लिया।

डॉ. मांडविया ने कहा कि भारत एक युवा देश है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार को उनकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। सरकार उन्हें सशक्त बनाने तथा सर्वोत्तम अवसर प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता के बारे में बात करते हुए उन्होंने युवाओं से 'माई भारत' प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के भविष्य को बदलते समय के अनुरूप ढालने के लिए यह मंच पेश किया है। आने वाले दिनों में 'माई भारत' युवाओं की सभी जरूरतों के लिए एक समग्र (वन-स्टॉप) समाधान के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा, 'चाहे सूचना हो, करियर संबंधी आवेदन हो या फॉर्म जमा करना हो, यह मंच न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच योग्य होगा।'

इस कार्यक्रम के दौरान 'युवा संवाद' नाम से एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। इस विशेष सत्र में डॉ. मांडविया युवाओं के साथ संवाद में शामिल हुए। कई युवा प्रतिभागियों ने समाज में सार्थक योगदान देने की अपनी क्षमता एवं दृढ़ संकल्प को रेखांकित करते हुए चुनौतियों पर काबू पाने और अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने की अपनी प्रेरक कहानियां साझा कीं। केंद्रीय मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कार्यप्रणालियों में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री की 'प्लांट 4 मदर' पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि और यूनिसेफ युवाह बोर्ड की सह-अध्यक्ष सिंथिया मैककैफ्रे ने युवाओं को वैश्विक कार्रवाई में शामिल करने के महत्व पर जोर दिया।

क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस

संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह दुनिया के भविष्य को आकार देने में युवाओं के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष की थीम 'क्लिक से प्रगति तक: सतत विकास के लिए युवाओं की डिजिटल राह' इस बात पर जोर देती है कि कैसे डिजिटलीकरण हमारी दुनिया को बदल रहा है और सतत विकास में तेजी लाने के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान कर रहा है। मोबाइल उपकरण, सेवाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियां सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को आगे बढ़ाने में सहायक हैं।■

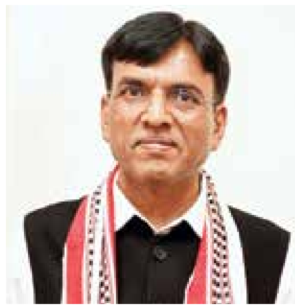

युवा सिर्फ कल के नेता ही नहीं, बल्कि आज के परिवर्तन के वाहक भी हैं। आपकी ऊर्जा और आपका नवाचार एवं समर्पण माननीय प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की कुंजी हैं।

डॉ मनसुख मांडविया
केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री

स्किल डवलपमेंट पर ए

युवा सहकार टीम

राष्ट्रीय युवा सहकारी समिति लिमिटेड (एनवाईसीएस) इस वर्ष अपनी स्थापना के 25 वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर 25 अगस्त, 2024 को हुए एनवाईसीएस की 23वीं वार्षिक आम सभा में समिति ने अपनी भविष्य की रणनीति का ब्यौरा शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया। एनवाईसीएस के प्रेसिडेंट श्री चंद्र प्रकाश साहू ने वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह वर्ष युवा सशक्तिकरण में युवाओं के इस सहकारी संगठन के समर्पण और उपलब्धियों की महत्वपूर्ण यात्रा को उजागर करता है। उन्होंने संगठन की 25 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए आगे की रूपरेखा की जानकारी दी। साहू ने कहा कि पिछले दो-तीन वर्षों से एनवाईसीएस का फोकस स्किल डेवलपमेंट पर

नवाईसीएस का फोकस

है। देश के हर युवा को सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी मिलना मुश्किल है। मगर कौशल विकास के माध्यम से रोजगार से जुड़ी युवाओं की चुनौतियों का समाधान बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखकर ही संगठन आगे की योजनाओं पर काम कर रहा है।

एआरजीबीएम में एनवाईसीएस के देशभर के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दूसरे सत्र में प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का सत्र रखा गया था जिसमें विविध दृष्टिकोण और विचार सामने आए जो सहकारी संगठन के लिए मूल्यवान रहा। बोर्ड के सदस्य इस फीडबैक के आधार पर आगे की कार्रवाई करने और नई पहलों की योजना बनाएंगे। इस तरह का सहयोगात्मक दृष्टिकोण अक्सर अधिक प्रभावी और नवाचार आधारित समाधानों की ओर ले जाता है। एनवाईसीएस के बोर्ड ने इस मौके पर वित्त वर्ष 2023-24 में अच्छा प्रदर्शन करने वाली शाखाओं को पुरस्कृत भी किया।

युवाओं को सशक्त बनाने की पहल

भारत के 15 से 35 वर्ष की आयु के युवा देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के पीछे एक प्रेरक शक्ति हैं। उनका नवाचार रचनात्मकता और उत्साह उन्हें सतत विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करता है।

विशाल सिंह

अध्यक्ष, एनसीसीएफ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच है कि हर युवा को सीखने, कौशल विकास और कुछ नया करने का अवसर मिले तभी हम 2047 तक सपनों के भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं को लागू किया है। इससे दुनिया के सबसे युवा देश भारत को सशक्त बनाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री युवाओं की शक्ति को वैश्विक संपत्ति के रूप में देखते हैं। उनका दृष्टिकोण युवाओं को सशक्त बनाना और भारत की प्रगति एवं दुनिया की भलाई के लिए उनकी क्षमताओं का उपयोग करना है।

उनके प्रयासों में स्किल इंडिया शामिल है जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और रोजगार क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देना और स्टार्टअप का समर्थन करना है, तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना, अटल इनोवेशन मिशन छात्रों के बीच नवाचार और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया का उद्देश्य देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करना है। ये कदम सामूहिक रूप से युवाओं को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक कौशल अवसर और समर्थन से सक्षम करने का प्रयास कर रहे हैं जो अंततः भारत के समग्र विकास में योगदान दे रही है।

श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी बहुपक्षीय योजना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है। अपनी जीवंत और गतिशील युवा आबादी के साथ भारत उस विशाल क्षमता और महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है जिसे उसके युवा एक टिकाऊ और प्रगतिशील दुनिया के निर्माण में निभा सकते हैं। भारत शांति और एकता की विश्वव्यापी भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करता रहा है इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं- एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य।

सतत विकास, उद्यमिता, डिजिटलीकरण और नवाचार जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करते भारत के युवा वैश्विक एजेंडा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हुए नए दृष्टिकोण और विचार ला सकते हैं।

सतत विकास के लिए उत्प्रेरक

भारत के 15 से 35 वर्ष की आयु के युवा देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के पीछे एक प्रेरक शक्ति हैं। उनका नवाचार रचनात्मकता और उत्साह उन्हें सतत विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करता है। हमारे युवा वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं, विचारों का आदान-प्रदान और आम सहमति बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। यह सामूहिक प्रयास सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकता है और 21वीं सदी में काम के भविष्य को आकार दे सकता है।

उद्यमिता को बढ़ावा देना

तकनीकी व्यवधानों और बदलते रोजगार

परिदृश्यों के सामने उद्यमिता व छोटे और मध्यम आकार के उद्यम (एसएमई) आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टार्टअप इंडिया नीति ने स्टार्टअप के लिए एक संपन्न परिस्थितिकी तंत्र का प्रतिपालन किया है जिससे कई नए उद्यम उभरे हैं और नौकरी के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। युवा अपने समकक्षों और नीति निमार्ताओं को समावेशी आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में उद्यमिता को समर्थन और बढ़ावा दोनों के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

डिजिटलीकरण का उपयोग

भारत की डिजिटल क्रांति ने देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है, डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त कर काम और विकास के नए अवसर पैदा किए हैं। डिजिटल इंडिया जैसी पहल के माध्यम से देश में डिजिटल प्रशासन दूरस्थ कार्य और सामग्री निर्माण में वृद्धि देखी गई है। भारत की डिजिटल उपलब्धियों को उजागर करने और यह दिखाने के लिए कि कैसे डिजिटलीकरण अंतर को समाप्त कर समावेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है और तेजी से बदलती दुनिया में युवाओं की क्षमता के अनुसार रास्ते खोले जा सकते हैं।

भविष्य का निर्माण

आज दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित और कुशल कार्यबल की आवश्यकता है। बदलते परिदृश्य में अनुकूल रहने और आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है जो उन्हें वर्तमान समय के अनुकूल कौशल से सुसज्जित करें। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति नवीन शिक्षण विधियों, आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान क्षमताओं के माध्यम से युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के महत्व पर जोर देती है। भविष्य उन्मुख कुशल कार्यबल विकसित करने के उद्देश्य से विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार की जटिलताओं से निपटने के लिए सशक्त बनाता है।

युवाओं को सशक्त बनाना

समावेशी निर्णय लेने और नीति निर्माण के लिए शासन में युवाओं की भागीदारी आवश्यक है। भारत ने छात्र केंद्रित शासन और नीति फेलोशिप जैसी पहलों के माध्यम से शासन को आकार देने में युवाओं की सक्रिय एजेंसी को मान्यता दी है। युवा केंद्रित मॉडलों का प्रदर्शन करके भारत अन्य देशों को युवाओं के लिए नीति निर्माण में योगदान देने, अलग अलग पीढ़ी के बीच संवाद और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है।

भारत प्रगतिशील दुनिया के निर्माण में युवाओं की शक्ति का लाभ उठाने का महत्वपूर्ण अवसर पेश कर रहा है। सतत विकास, उद्यमिता, डिजिटलीकरण और नवीनीकरण पर ध्यान केंद्रित करके भारत के युवा विश्व में सकरात्मक बदलाव ला सकते हैं। सक्रिय युवा भागीदारी के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और युवा दृष्टिकोण का लाभ उठाया जा सकता है और अधिक समावेशी और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।■

स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देना और स्टार्टअप का समर्थन करना है, तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना, अटल इनोवेशन मिशन छात्रों के बीच नवाचार और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने और मेक इन इंडिया का उद्देश्य देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

सहकारिता में बढ़ रही युवाओं की भागीदारी

अभिषेक सिंह राठौर

महाप्रबंधक, एनवाईसीएस

आज के युग में जब तेजी से बदलती आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हमारे सामने हैं, हमें यह समझने की जरूरत है कि युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। देश के विकास में युवाओं की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती। यही वजह है कि हमें युवाओं को सहकारिता आंदोलन से जोड़ने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

सहकारी आंदोलन एक ऐसा तंत्र है जो समाज के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आंदोलन न केवल आर्थिक लाभ की दिशा में काम करता है, बल्कि सामाजिक समरसता, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास को भी प्रोत्साहित करता है। सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पर आधारित होती हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया में समानता और पारदर्शिता बनी रहती है।

युवाओं को सहकारी आंदोलन से जोड़ने के कई लाभ हो सकते हैं। युवा पीढ़ी में कुछ नया और अलग करने की अतुल्य क्षमता होती है। सहकारी संस्थाओं में युवाओं की भागीदारी से नए विचार, योजनाएं और रणनीतियां सामने आ सकती हैं, जो संस्थाओं की कार्यक्षमता को बढ़ा सकती हैं। इन संस्थाओं का हिस्सा बनकर युवा न केवल अपने रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। सहकारी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी से युवाओं को समाज के विभिन्न वर्गों के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है, जिससे सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है।

> **सहकारी आंदोलन में युवाओं की सक्रिय भागीदारी से युवाओं को समाज के विभिन्न वर्गों के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है, जिससे सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है।**

युवाओं को सहकारी आंदोलन से जोड़ने के लिए उन्हें इसके लाभ और महत्व के बारे में सही जानकारी और शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सहकारी आंदोलन पर कार्यशालाएं और चर्चा सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। इसके अलावा, विभिन्न मीडिया माध्यमों के द्वारा भी सहकारी आंदोलन के लाभों की जानकारी समाज तक पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को नई सहकारी संस्थाओ का अधिक से अधिक पंजीकरण करके एवं युवाओं को सहकारी संस्थाओं में शामिल करने के लिए विशेष योजनाएं और प्रोत्साहन प्रदान करने चाहिए। जैसे सहकारी उद्यमों में निवेश के लिए विशेष अनुदान, युवा उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और सहकारी संस्थाओं में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

युवाओं को सहकारिता से जोड़ना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यकता है। युवाओं की ऊर्जा, विचारशीलता और सक्रियता से सहकारी आंदोलन को एक नई दिशा और गति मिल सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी अगली पीढ़ी इस आंदोलन की पूरी क्षमता को समझे और इसका हिस्सा बने, ताकि हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर समाज की दिशा में आगे बढ़ सकें।

पिछले 10 वर्षों से नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) जो एक युवा सहकारी संस्था है, के साथ काम करके देश और युवा पीढ़ी के लिए सहकारिता के महत्व एवं जरूरत को बहुत करीब से समझने का मौका मिला। एनवाईसीएस एक सूत्री कार्ययोजना 'युवाओं का उत्थान' के लिए अलग-अलग कार्यक्रम के माध्यम से इसे आगे बढ़ा रहा है। यह कौशल विकास, खेल गतिविधि, माइक्रो फाइनेंस, कृषि क्षेत्र, युवा एक्सपो जैसे अनेक कार्यक्रम चला रहा है। देश का युवा अब बड़ी संख्या में एनवाईसीएस के साथ जुड़ रहा है। एनवाईसीएस इस वर्ष अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को और विस्तृत रूप में युवाओं तक ले जाने की प्रतिबद्धता के साथ आगे का लक्ष्य तय कर रहा है।■

पीएम जन-धन योजना का एक दशक

बिना बिचौलिए लाभार्थियों को मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ

पीएमजेडीवाई ने गरीबों को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल किया और हाशिये के समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

पीएमजेडीवाई की शुरूआत से अब तक 53.14 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिली बैंकिंग सुविधा, खातों में कुल 2.31 लाख करोड़ रुपये जमा

करीब 55.6 प्रतिशत जन-धन खाताधारक महिलाएं और लगभग 66.6 प्रतिशत जन-धन खाते ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में

युवा सहकार टीम

दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने सफलता का एक दशक पूरा कर लिया है। इस दौरान इस योजना ने देश के करोड़ों युवाओं, महिलाओं और गरीबों के सपनों को न सिर्फ नई ऊंचाई देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया है, बल्कि बिना किसी बिचौलिए के पात्र लाभार्थियों तक सरकारी सब्सिडी और भुगतान को पहुंचाने, निर्बाध लेनदेन और बचत के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का काम किया है जिसके माध्यम से बैंक एवं वित्तीय संस्थान समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में समर्थ हुए हैं। 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस वित्तीय समावेशन योजना के तहत किए गए प्रयासों ने प्रभावी तौर पर परिवर्तनकारी एवं दिशात्मक बदलाव किए हैं। इस योजना के तहत बिना किसी शुल्क या रखरखाव शुल्क के उन गरीबों का बैंक खाता खोला जाता है जिनका कोई बैंक खाता नहीं

इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले एक दशक में 53.13 करोड़ लोगों के जन-धन खाते खोलकर उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया है। इन बैंक खातों में 2.3 लाख करोड़ रुपये जमा हुए हैं

है। इस खाते में न्यूनतम राशि रखने की भी जरूरत नहीं होती है।

पीएम जन-धन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) में बड़े मददगार साबित हुए हैं। बिना किसी बिचौलिए और नुकसान के विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी वितरित करने और मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए भुगतान का यह महत्वपूर्ण ढांचा साबित हुआ है। इसके माध्यम से सरकार सब्सिडी एवं सामाजिक लाभ को सीधे तौर पर वंचितों के बैंक खातों में सुरक्षित तरीके से सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर पा रही है। जन-धन खाते को आधार और मोबाइल से लिंक करने से यह संभव हो पाया है। इसके अलावा ये खाते जन सुरक्षा योजनाओं (सूक्ष्म बीमा योजनाओं) के जरिये असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को जीवन एवं दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले एक दशक (14 अगस्त, 2024 तक) में 53.13 करोड़ लोगों के जन-धन खाते खोलकर उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया है। इन बैंक खातों में 2.3 लाख करोड़ रुपये जमा हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप 36 करोड़ से अधिक निःशुल्क रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। इन रुपे कार्ड पर खाताधारकों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। पीएमजेडीवाई खाताधारकों को आपातकालीन स्थितियों के दौरान 10 हजार रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है। इस योजना के तहत 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण या कस्बाई क्षेत्रों में खोले गए हैं और 55 प्रतिशत खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं। 10 साल में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से मनरेगा, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के 38 लाख करोड़ रुपये इन खातों में हस्तांतरित किए गए हैं।

जन-धन योजना के 10 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वित्तीय समावेशन पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव की सराहना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "सभी लाभार्थियों को बधाई और उन सभी का अभिवादन जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने के लिए काम किया। जन-धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सम्मान देने में सर्वोपरि रही है।" केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, 'पीएम जन-धन योजना' ने करोड़ों गरीबों के वित्तीय समावेशन से उनके सपनों को नई ऊंचाई देकर अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया है। देश की अर्थव्यवस्था में अकल्पनीय परिवर्तन लाने वाली इस योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने की सभी लाभार्थियों को बधाई।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री

पीएमजेडीवाई की प्रमुख उपलब्धियां

प्रधानमंत्री जन-धन योजना विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इसकी परिवर्तनकारी ताकत और डिजिटल नवाचारों ने भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांतिकारी बदलाव किया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान इस योजना के सफल कार्यान्वयन ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।

- **खातों की संख्याः** प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत 14 अगस्त, 2024 तक खोले गए खातों की कुल संख्या 53.13 करोड़ है। इसमें 55.6 प्रतिशत (29.56 करोड़) खाताधारक महिलाएं हैं और 66.6 प्रतिशत (35.37 करोड़) खाते ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में हैं।
- **खातों में कुल जमाः** पीएम जन-धन योजना के तहत खोले गए खातों में कुल जमा रकम 2,31,236 करोड़ रुपये है। अगस्त 2015 के मुकाबले अगस्त 2024 तक इन खातों की संख्या में 3.6 गुना वृद्धि हुई है, जबकि इस अवधि के दौरान जमा राशि में करीब 15 गुना की वृद्धि हुई है।
- **प्रति खाता औसत जमाः** जन-धन खातों में प्रति खाता औसत जमा रकम (14 अगस्त, 2024 तक) 4,352 रुपये है। अगस्त 2015 के मुकाबले प्रति खाता औसत जमा रकम में 4 गुना वृद्धि हुई है। औसत जमा रकम में वृद्धि खातों के बढ़ते उपयोग और खाताधारकों में बचत की आदत विकसित होने का संकेत है।
- **रुपे कार्डः** प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गए खातों के खाताधारकों को 36.14 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। समय के साथ-साथ रुपे कार्ड की संख्या और उपयोग में वृद्धि हुई है।

पीएमजेडीवाई की सफलता इसके मिशन मोड वाले दृष्टिकोण, नियामकीय समर्थन, सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी और बायोमेट्रिक पहचान के लिए आधार जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की वजह से संभव हुई है। पीएम जन-धन योजना ने लोगों को बचत करने में सक्षम बनाया है। साथ ही इसने औपचारिक तौर पर लेनदेन के बिना किसी रिकॉर्ड वाले लोगों के लिए भी ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित की है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने संदेश में कहा, ''वित्तीय समावेशन एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक सभी की आसान पहुंच आवश्यक है। यह गरीबों को आर्थिक मुख्यधारा में एकीकृत करता है और हाशिए के समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक खाते, लघु बचत योजनाएं, बीमा एवं ऋण सुविधा सहित तमाम सार्वभौमिक, सस्ती एवं औपचारिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हुए पीएम जन-धन योजना ने पिछले एक दशक में देश के बैंकिंग एवं वित्तीय परिदृश्य को बदल दिया है। इसने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को पात्र लाभार्थियों के खाते में त्वरित, निर्बाध एवं पारदर्शी तरीके से हस्तांतरित करने में सक्षम बनाया है और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है।''

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा, ''पीएमजेडीवाई महज एक योजना नहीं है, बल्कि यह एक परिवर्तनकारी अभियान है, जिसने बैंकिंग सेवाओं से वंचित तमाम लोगों को वित्तीय आजादी प्रदान की है और उनमें वित्तीय सुरक्षा की भावना पैदा की है। सभी हितधारकों, बैंकों, बीमा कंपनियों और राज्य सरकारों के समर्थन से अब हम वित्तीय तौर पर कहीं अधिक समावेशी समाज की ओर बढ़ रहे हैं। पीएमजेडीवाई को देश के वित्तीय समावेशन में गेम चेंजर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन-धन योजना न केवल शासन के मिशन मोड का एक प्रमुख उदाहरण है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि अगर सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, तो वह क्या हासिल कर सकती है।''■

> **वित्तीय समावेशन एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक सभी की आसान पहुंच आवश्यक है। यह गरीबों को आर्थिक मुख्यधारा में एकीकृत करता है और हाशिए के समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**
>
> **श्रीमती निर्मला सीतारमण**
> **केंद्रीय वित्त मंत्री**

सोशल मीडिया से बढ़ रहा है सहकारिता का दायरा

सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सहकारिता मॉडल, इसके लाभ और सामुदायिक विकास में सहकारिता के सहयोग की जानकारी दी जा सकती है। सोशल मीडिया पर सहकारिता व्यवसायिक मॉडल की जानकारी, इसका इतिहास और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में इसके योगदान की भी जानकारी दी जा सकती है।

युवा सहकार टीम

सहकारी क्षेत्र समुदाय आधारित पहलों, आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज जबकि संचार के साधनों की वजह से दुनिया बहुत छोटी हो गई है, ऐसे में सोशल मीडिया एक मजबूत माध्यम बन गया है। इसका प्रयोग सहकारिता की गतिविधियों के प्रति लोगों को जागरूक करने और कार्यप्रणाली को हितधारकों तक पहुंचाने और नीतियों की जानकारी देने के लिए किया जा सकता है। हालांकि सोशल मीडिया का प्रभावी तरीके से प्रयोग करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति बनाने की जरूरत होती है, जिससे सहकारिता क्षेत्र की विशिष्टता को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके।

सोशल मीडिया की रणनीतियों को समझने से पहले यह जरूरी है कि सहकारिता की अहम व जरूरी बातों को समझ लिया जाए। सहकारिता सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत गठित ऐसा संगठन है जो सदस्यों के लाभ के लिए सामुहिक रूप से काम करता है। इनके काम करने का दायरा बहुत विस्तृत होता है, सहकारी संगठन कृषि, वित्तीय सेवाएं, आवासीय, मत्स्य, डेयरी, उपभोक्ता, हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक व्यावसायों के साथ ही सहकारी संगठन महत्वपूर्ण सिद्धतों जैसे कि स्वैछिक सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता का भी पालन करते हैं। यह सहकारी समितियों को अपने सदस्यों, हितधारकों और व्यापक समुदायों को ऑन लाइन और ऑफ लाइन दोनों ही तरीकों से जुड़ने के विकल्प उपलब्ध कराती है।

सोशल मीडिया पर पहुंच बढ़ाने की रणनीतियां

किसी भी सफल सहकारिता संगठन की ताकत उसके मूल्यों और सिद्धातों में होती है, जिससे सामुदायिक सहभागिता, सघनता और एकजुटता बनी रहती है। सहकारिता के लिए सोशल मीडिया की सामग्री तैयार करते समय, सहकारी समितियों को अपने सदस्यों के साथ तालमेल बैठाने के लिए खुद को पारंपरिक व्यवसायों से अलग करने के लिए इन मूल्यों और सिद्धातों का प्रदर्शन करना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए कंटेंट कुछ इस तरह तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें इसके सदस्यों को मिलने वाले लाभों और सदस्यों की सफलता की कहानियों को प्रमुखता से शामिल करना चाहिए। सोशल मीडिया की सामग्री को सहकारिता के सिद्धातों

के साथ मिलाकर देने से सदस्य संगठन के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे।

शिक्षा और जानकारी का हुआ विस्तार

सहकारी समितियां अक्सर विशिष्ट बाजारों की सेवा करती हैं या फिर विशिष्ट सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान भी करती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सहकारिता मॉडल, इसके लाभ और सामुदायिक विकास में सहकारिता के सहयोग की जानकारी दी जा सकती है। सोशल मीडिया पर सहकारिता व्यवसायिक मॉडल की जानकारी, इसका इतिहास और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में इसके योगदान की भी जानकारी दी जा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग सहकारिता के सिद्धांतों जैसे, शिक्षा, प्रशिक्षण और जानकारी आदि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा सकता है। सूचना के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करके सहकारी समितियां स्वयं को संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी के रूप में स्थापित कर सकती हैं, इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई जानकारी सहकारी संगठनों के प्रति लोगों में रूचि बढ़ा सकती हैं।

समूह सदस्यों की संगठन में बढ़ी भागीदारी

सदस्य सहकारिता संगठन का आधार होते हैं, और सोशल मीडिया सदस्यों की संगठन में सक्रिय और सार्थक भागीदारी को बढ़ा सकता है। सदस्यों को सहकारी संगठन से ऑनलाइन जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है, जिससे सदस्य विषयों की चर्चा में भाग ले सकते हैं और अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। सहकारी समितियां मतदान, सर्वेक्षण और प्रश्नोत्तर सत्रों के माध्यम से सदस्यों से प्रतिक्रिया मांग सकती हैं। इससे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिशिचत हो सकती है। समुदाय और भागीदारी की भावना पैदा करके सहकारी समितियां सदस्यों की वफादारी और वकालत

को मजबूत कर सकती हैं। जैविक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं और विपणन के माध्यम से अपनी पहुंच का विस्तार कर सकती हैं।

सफलता की कहानियां साझा करना

सोशल मीडिया के विस्तृत प्लेटफार्म पर संगठन से जुड़ी सफलता की कहानियां प्रकाशित की जा सकती हैं। ऐसी कहानियां मिशन की सफलता को सही तरीके से प्रस्तुत करेंगी और मिशन को आगे बढ़ाने में सहायक होंगी। सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री प्रकाशित की जा सकती है, जिसमें संगठन से जुड़े सदस्यों के संघर्ष की कहानियां हों, और किस तरह सहकारिता ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया, कैसे सहकारिता समुदायों और देश की आर्थिक तरक्की में भी अहम भूमिका निभा रही है। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत सदस्यों, कर्मचारियों और सामुदायिक साझेदारी के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, जिन्होंने सहकारिता सिद्धांतों और मूल्यों का अपनी गतिविधियों में गंभीरता से अनुपालन किया है। सामग्री के अलावा सोशल मीडिया पर तस्वीर, वीडियो, इंफोग्राफिक्स के माध्यम से भी जानकारियां साझा की जा सकती हैं। सहकारी संगठन, अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में दृश्यों या फिर चित्रों के माध्यम से आकर्षक पोस्ट साझा कर सकते हैं।■

सदस्य सहकारिता संगठन का आधार होते हैं, और सोशल मीडिया सदस्यों की संगठन में सक्रिय और सार्थक भागीदारी को बढ़ा सकता है। सदस्यों को सहकारी संगठन से ऑनलाइन जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है, जिससे सदस्य विषयों की चर्चा में भाग ले सकते हैं और अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं।

कौशल विकास के लिए फ्लिपकार्ट से एमओयू

कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी की मौजूदगी में भारत सरकार और फ्लिपकार्ट के बीच हुआ एमओयू।

युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने फ्लिपकार्ट की सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी से किया एमओयू

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत हुई इस साझेदारी का लक्ष्य ई-कॉमर्स और आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्रों में युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है

कारीगरों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए फ्लिपकार्ट 5 वर्ष से चला रही समर्थ प्रोग्राम

युवा सहकार टीम

देश के करोड़ों युवाओं का कौशल विकास करने और उन्हें उद्योग एवं वैश्विक मांगों के मुताबिक तैयार करने को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। यह वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भी जरूरी है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का दायरा बढ़ाया जा रहा है और इसे व्यापक बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी की मौजूदगी में घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) किया है।

यह एमओयू फ्लिपकार्ट की सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी (एससीओए) से हुआ है। इस एमओयू का मकसद पूरे देश में रोजगार पाने योग्य हजारों युवाओं को कौशल युक्त बनाना है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत हुई इस साझेदारी का लक्ष्य युवाओं को कौशल युक्त बनाकर ई-कॉमर्स और आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्रों में उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। फ्लिपकार्ट की टीम उम्मीदवारों को 7 दिवसीय गहन क्लासरूम प्रशिक्षण के साथ एक समग्र अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके बाद फ्लिपकार्ट की फैसिलिटी (जिन जगहों पर रोजमर्रा के काम होते हैं) में उन्हें 45 दिवसीय व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है। इस विशेष प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम के जरिये युवा शक्तियों को सफल करियर के लिए तैयार किया जाता है ताकि देश की आर्थिक वृद्धि में वे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

भारत के कारीगरों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के समर्थ प्रोग्राम के पांच साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में यह एमओयू किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप वैश्विक मांगों को देखते हुए युवाओं को कौशल युक्त बनाने पर सरकार के दृढ़निश्चय पर जोर दिया। उन्होंने

कहा, "भारत सरकार कारीगरों को सशक्त बनाने और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग विविध शिल्पों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है। फ्लिपकार्ट समर्थ की यात्रा के उत्सव में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और फ्लिपकार्ट की सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी (एससीओए) के बीच सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया। यह प्रयास हमारे युवाओं को आधुनिक बाजार में आगे बढ़ने के लिए कौशल से युक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पारंपरिक शिल्प को डिजिटल क्षेत्र में एकीकृत करके हम मजबूत साझेदारी बना रहे हैं और समर्थ कार्यक्रम के माध्यम से नवाचार को अपना रहे हैं। इससे भारत के एमएसएमई क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।"

उद्योग सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि उद्योग के साथ साझेदारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इंटर्नशिप कार्यक्रमों और समर्थ जैसे प्रयासों के माध्यम से हम युवाओं के लिए विकसित हो रही कार्य संस्कृति के साथ जुड़ने और भविष्य के लिए आवश्यक दक्षता हासिल करने के अवसर खोल रहे हैं। वैश्विक आकांक्षाओं वाले घरेलू ब्रांड फ्लिपकार्ट ने महिला उद्यमियों और वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को सशक्त बनाकर अपना प्रभाव प्रदर्शित किया है। इससे 18 लाख आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित अपनी एकेडमी के शुभारंभ के साथ फ्लिपकार्ट भारत के विकास को आगे बढ़ाते हुए व्यापक ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देना जारी रखे हुए है।

इस कार्यक्रम में 250 से अधिक उद्योग जगत के दिग्गजों, विक्रेताओं, कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और एसएचजी ने भाग लिया। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना और उसे उन्नत करना था। फ्लिपकार्ट समूह के कॉरपोरेट मामलों के मुख्य अधिकारी रजनीश कुमार ने इस मौके पर कहा, "समर्थ 5 वर्षीय यात्रा उत्सव कार्यक्रम पूरे भारत में कारीगरों, बुनकरों और एमएसएमई को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। समर्थ पहल के माध्यम से हमने अपनी यात्रा के पिछले 5 वर्षों में आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसके माध्यम से 100 से अधिक पारंपरिक कला रूपों को संरक्षित किया गया है और हजारों विक्रेताओं की वृद्धि को बढ़ावा दिया गया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ हमारी साझेदारी भारत के युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल से युक्त करेगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे अतीत की विरासत भविष्य की पीढ़ियों के हाथों में फलती-फूलती रहेगी।"

फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम में कारीगर सशक्तिकरण के भविष्य पर एक पैनल चर्चा भी हुई। पैनल में एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव अतीश कुमार सिंह, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र पायल, बीयूनिक की सह-संस्थापक एवं निदेशक सिम्मी नंदा और अखिल भारतीय कारीगर और शिल्पकार कल्याण संघ की कार्यकारी निदेशक मीनू चोपड़ा ने आज के तेजी से विकसित हो रहे माहौल में भारत के कारीगर समुदाय के भविष्य, कौशल विकास के महत्व और बाजार पहुंच के विस्तार में ई-कॉमर्स की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में चर्चा की। फ्लिपकार्ट ने इस दौरान अपने ऐप पर 'समर्थ स्टोरफ्रंट' इंडियन रूट्स का अनावरण किया। यह वर्चुअल प्लेटफॉर्म कारीगरों, बुनकरों और एमएसएमई को राष्ट्रीय बाजार तक अभूतपूर्व पहुंच प्रदान करता है। इससे उन्हें पूरे भारत में 50 करोड़ से अधिक ग्राहकों को अपने अद्वितीय उत्पाद प्रदर्शित करने में मदद मिलती है।

इस कार्यक्रम ने सरकार से जुड़े दिग्गजों, उद्योग विशेषज्ञों और प्रमुख हितधारकों के लिए डिजिटल युग में कारीगर सशक्तिकरण के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। इस दौरान लाखों लोगों के लिए स्थायी आजीविका बनाने के पारंपरिक शिल्प कौशल को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने के महत्व को रेखांकित किया गया।■

फ्लिपकार्ट समर्थ की यात्रा के उत्सव में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और फ्लिपकार्ट की सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी (एससीओए) के बीच सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया। यह प्रयास हमारे युवाओं को आधुनिक बाजार में आगे बढ़ने के लिए कौशल से युक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

गांवों में घर-घर पानी पहुंचाएगी पैक्स

रायपुर में सहकारिता समीक्षा बैठक में शिरकत करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं अन्य।

छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में पानी समिति के रूप में पैक्स का अमित शाह ने किया शुभारंभ

ग्रामीण जनता तक पैक्स की अनेक गतिविधियों का लाभ पहुंचाने के लिए हर पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर बनाने पर जोर

देश के सभी पैक्स, सहकारी संस्थाओं और सभी मंडियों के व्यापारियों से जिला सहकारी बैंकों में खाता खोलने का आह्वान

युवा सहकार टीम

छत्तीसगढ़ के गांवों में पीने के पानी की समस्या को दूर करने की जिम्मेदारी अब प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की होगी। राज्य के सभी 33 जिलों में पानी समिति के रूप में पैक्स का शुभारंभ किया गया है। ये पैक्स घर-घर पानी की सुविधा पहुंचाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के सपने को साकार करने के लिए देश की सभी पंचायतों तक सहकारी समितियों का विस्तार किया जा रहा है। सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के साथ ही सभी पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) बना देने से देश की ग्रामीण जनता को पैक्स की अनेक गतिविधियों का लाभ सीधे मिल सकेगा।

पिछले दिनों केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में सहकारिता के विस्तार की समीक्षा करने के लिए रायपुर पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने राज्य के सभी 33 जिलों में पानी समिति के रूप में पैक्स का शुभारंभ किया। उन्होंने सहकारिता के माध्यम से गांव, गरीब और आदिवासियों की उन्नति के लिए प्रदेश सरकार का आह्वान करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण के तहत राज्य सरकार को पशुपालन, कृषि, जनजातीय मामले और सहकारिता विभागों को मिलकर काम करना चाहिए। राज्य सरकार को सहकारी विकास को गति देने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को संपूर्ण जनजातीय विकास के लिए एक नई पब्लिक डेयरी योजना बनानी चाहिए, जो पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी संस्था का काम करे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 2058 पैक्स ने मॉडल बायलॉज को अपना लिया है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उपयोग छत्तीसगढ़ में सहकारिता की पहुंच से बाहर बचे पंचायतों को ढूंढने के लिए करना चाहिए। इससे सहकारिता के विस्तार में मदद मिलेगी।

इस मौके पर श्री शाह ने कहा कि किसानों के कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए पैक्स द्वारा नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण होना चाहिए। एथेनॉल उत्पादन के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और राज्यों के बीच अनुबंध होना चाहिए, जिससे किसानों को मक्के की खेती के प्रति प्रोत्साहित किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में मक्के और दलहन की खेती को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देते हुए श्री शाह ने इसके लिए राज्य के कृषि विभाग को पहल करने का सुझाव दिया।

अमित शाह ने कहा कि देश की सभी मंडियों के सभी व्यापारियों, पैक्स और सहकारी संस्थाओं का खाता जिला सहकारी बैंक में खोलना अनिवार्य होना चाहिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में कुल छह जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (डीसीसीबी) हैं। राज्य में पैक्स के विस्तार की दृष्टि से उन्होंने निकट भविष्य में कम से कम चार और डीसीसीबी की स्थापना का सुझाव दिया।

यीडा गांवों में शुरू करेगा कौशल विकास केंद्र

युवाओं को मिलेगा रोजगार प्रशिक्षण

युवा सहकार टीम

केंद्र सरकार युवाओं का कौशल विकास करने को लेकर प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब उत्तर प्रदेश के 1,149 गांवों में कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे जिनमें युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) इस सकारात्मक पहल की शुरूआत जल्दी ही करेगा। पहले चरण में 96 गावों में कौशल विकास केंद्र शुरू किए जाएंगे।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में राज्य के गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा व आगरा जिले के 1,149 गांव अधिसूचित हैं। फेज एक में गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर के 171 गांव यीडा के मास्टर प्लान में शामिल हो चुके हैं, लेकिन प्राधिकरण ने अभी तक 96 गांवों की जमीनों का ही अधिग्रहण किया है। प्रभावित गांवों के लोग और किसान संगठन स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की मांग उठाते रहे हैं जिसे देखते हुए प्राधिकरण ने यह पहल करने की घोषणा की है। इस पहल के तहत प्राधिकरण कौशल विकास केंद्र खोलेगा, जबकि प्रशिक्षण की जिम्मेदारी प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों पर होगी। वे अपने जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देकर युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेंगे।

यीडा के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है, 'पहले चरण में अधिग्रहित सभी 96 गांवों में उद्योगों के सहयोग से कौशल विकास केंद्र शुरू किए जाएंगे। प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों की ओर से इन केंद्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उद्योग अपनी जरूरत के हिसाब से युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार लायक बनाएंगे।' गांवों में खोले जाने वाले कौशल विकास केंद्रों में जिन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा उनका चयन नक्शा 11 के आधार पर किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण का वास्तविक लाभ स्थानीय युवाओं को ही मिल सके। नक्शा 11 में किसान, उनकी जमीन, अधिग्रहण की स्थिति समेत अन्य जानकारी दर्ज होती है। उद्योगों में रोजगार के लिए स्थानीय युवाओं की पहचान भी नक्शा 11 से ही होगी।

> **यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) इस सकारात्मक पहल की शुरूआत जल्दी ही करेगा। पहले चरण में 96 गावों में कौशल विकास केंद्र शुरू किए जाएंगे।**

स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग को देखते हुए यीडा ने प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों के रोजगारों में स्थानीय युवाओं को 40 प्रतिशत आरक्षण देने का नियम लागू कर दिया है। कंपनी को औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए आवंटित भूखंड की लीज डीड की शर्त में इसे शामिल किया जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय युवाओं को रोजगार लायक बनाने की है। कौशल विकास केंद्र खुल जाने और युवाओं को प्रशिक्षण मिलने से इस चुनौती से आसानी से निपटा जा सकेगा।

कौशल विकास केंद्र खोलने के अलावा यीडा ने इन 96 गांवों में पुस्तकालयों के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में पांच गांवों में 30-30 लाख रुपये की लागत से ई-लाइब्रेरी का निर्माण कार्य चल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यीडा के सीईओ ने इनमें से एक डूंगरपुर रीलखा गांव में नवनिर्मित ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया।

गली-गली में शोर है, गली क्रिकेट का जोर है

मोहाली अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अपने अनोखे और खूबसूरत स्टेडियम के लिए मशहूर है तो उससे सटा चंडीगढ़ शहर गली क्रिकेट के लिए चर्चित हो रहा है। यूटी क्रिकेट एसोसिएशन (यूटीसीए) द्वारा आयोजित और एलेंजर्स, टाइनोर आदि द्वारा प्रायोजित गली क्रिकेट टूर्नामेंट की धूम अब चारों तरफ है। इस साल जुलाई में हुए इस टूर्नामेंट के दूसरे संस्करण के बाद इसकी चर्चा क्रिकेट प्रेमियों की जुबान पर है। इसकी सफलता और लोकप्रियता का आलम यह हो गया है कि लोग अभी से इसके अगले संस्करण का इंतजार करने लगे हैं।

गली क्रिकेट सीजन-1 का आयोजन पिछले वर्ष अप्रैल में हुआ था जिसमें 202 टीमों के 2,448 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सीजन-2 में लड़कों की 256 टीमों और लड़कियों की 46 टीमों के साथ कुल 3,624 बच्चे इस रोचक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। यूटीसीए और चंडीगढ़ पुलिस इन बच्चों को खेलने के लिए तैयार करके महत्वपूर्ण काम कर रही है। गली के बच्चे अपने बनाए सहज नियमों के साथ खेलते हैं। जैसे, 'मेरा बैट, मेरी बैटिंग, घेरे तक चौका, गेट के पार छक्का, बगल वाली आंटी की खिड़की टूटी तो तू गेम से बाहर...।' ऐसे बच्चों के लिए बहुप्रतीक्षित नीली पोशाक पहनने और असली स्टेडियम में खेलने का अवसर मिलना सपना सच होने जैसा है।

इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को कपड़े, जूते, खेल किट जैसे प्रोत्साहन देकर यूटीसीए क्रिकेट को प्रोत्साहित कर रहा है। गली-मोहल्लों के बच्चे जब भारतीय क्रिकेट टीम जैसी 'नीली पोशाक' पहनते हैं, तो वे खुद को तेंदुलकर या विराट कोहली के जैसा होना महसूस करते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के लिए राष्ट्रीय टीम में शामिल होना और खेलना संभव नहीं है, लेकिन यह खेल उन्हें निश्चित रूप से रोमांचित करता है और उनकी फिटनेस सुनिश्चित करता है। इस पहल का मकसद क्रिकेट को बढ़ावा देने के अलावा और भी बहुत कुछ है। चंडीगढ़ के समाज कल्याण विभाग का नशा मुक्ति अभियान टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाता है कि वे कभी भी ड्रग्स नहीं लेंगे।

यूटीसीए के अध्यक्ष संजय टंडन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट चंडीगढ़ पुलिस को सौंपते हुए।

प्रिया एस टंडन

इस टूर्नामेंट में क्या केवल युवाओं ने ही मौज-मस्ती की? जी नहीं, हाई प्रोफाइल टीमों के बीच भी प्रदर्शनी मैच आयोजित किए गए। जैसे, हाई कोर्ट जजों की टीम बार एसोसिएशन की टीम से 1 रन से हार गई। डीजीपी हरियाणा इलेवन ने डीजीपी पंजाब इलेवन के खिलाफ जीत हासिल की। इसी तरह, कलाकार इलेवन ने प्रेस इलेवन को हरा दिया।

यूटीसीए के गली क्रिकेट सीजन-1 को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई थी। इस बार इस टूर्नामेंट को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्डस में दर्ज किया गया। इस टूर्नामेंट का समापन 11 अगस्त को हुआ। यूटीसीए के अध्यक्ष संजय टंडन ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी एमएस यादव को सौंपा। संजय टंडन का प्रयास सीजन-3 में ज्यादा से ज्यादा टीमों को शामिल कर टूर्नामेंट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का है। सीजन-3 अगले साल अप्रैल में आयोजित किया जाएगा। टंडन की कोशिश है कि गली क्रिकेट का यह अनोखा और अनूठा आयोजन देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाये।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives, Always!

LIFIC

LINAC-NCDC FISHERIES BUSINESS INCUBATION CENTER (LIFIC)

For Cooperatives as Fisheries Bussiness

Set up by NCDC at LINAC
under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)
Department of Fisheries,
Ministry of Fisheries, AH & D, Govt of India

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
National Cooperative Development Corporation
Ministry of Cooperation, Govt of India

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

IFFCO KISAN DRONE

असरदार जोड़ी

नैनो यूरिया प्लस

सागरिका

नैनो डी ए पी

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड

इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017, भारत

फोन नंबर- 91-11-26510001, 91-11-42592626, वेबसाइट www.iffco.coop

इफको नैनो उर्वरकों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया स्कैन करें"